RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 09 JUNE TO 15 JUNE 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 42 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

गेल के विभाजन की योजना रद्द, कंपनी पाइपलाइन कारोबार में इनविट के जरिये कुछ हिस्सेदारी बेचेगी Page 2

टैक्स कंप्लायंस बढ़ाएगा नया पोर्टल Page 3

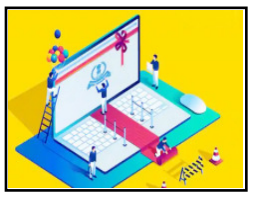

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के लिए 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी Page 5

editoria!

उद्यमों पर जोर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के योगदान को बढ़ाने का आह्वान किया है. फिलहाल जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 30 फीसदी है, जिसे 40 फीसदी करने पर उन्होंने जोर दिया है. हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्यमों के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 6.30 करोड़ उद्यमों में गैर-कृषि कार्यबल का 40 फीसदी हिस्से को रोजगार मिला हुआ है यानी इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक रोग सेवारत हैं. सेवा और मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन में इन उद्यमों का योगदान क्रमशः लगभग 25 और 33 फीसदी है. कोरोना महामारी की सबसे अधिक मार भी इसी क्षेत्र पर पड़ी है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों की ही अहम भूमिका होगी. इसलिए इनके विकास पर गडकरी का जोर देना समयानुकूल है. महामारी की पहली लहर से त्रस्त अर्थव्यवस्था को राहत देने के क्रम में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इन उद्यमों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के साथ अनेक नियमों में बदलाव भी किया गया था ताकि ये उद्यम फिर से खड़े हो सकें और अपनी संभावनाओं को साकार कर सकें. इस साल फरवरी में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्यमों को विकसित करने के लिए 15,700 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की थी. दुनियाभर में उत्पादन और कारोबार तंत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. बजट में इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने की बात भी कही गयी है. ऐसे उपायों से जहां उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, वहीं रोजगार की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. वित्तीय परिदृश्य में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या चिंताजनक है. इससे छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र भी अछूता नहीं है. इस क्षेत्र में एनपीए की वसूली के लिए सरकार ने एक अलग ढांचा बनाने का फैसला किया है. अब रिजर्व बैंक ने भी पुनर्संरचना पहल के तहत कर्जों की सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है. इससे राहत पाकर कई उद्यमों को नये उत्साह के साथ अपना विस्तार करने का अवसर मिलेगा. बीते साल-डेढ़ साल की मुश्किलों ने उनके सामने वित्त के अभाव का संकट खड़ा कर दिया है. ऐसे में न तो वे पुरानी देनदारी चुका पा रहे हैं और न ही नया ऋण लेने का साहस जुटा पा रहे हैं. छोटे उद्योगों के विकास के लिए बने बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने 16 हजार करोड़ रुपये की विशेष सुविधा भी प्रदान की है. केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की पहलों से स्थिति में सुधार की आशा है. महामारी के बाद की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर देश के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए छोटे व मझोले उद्यमों में बढ़ोतरी जरूरी है. इससे घरेलू मांग की पूर्ति के साथ निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया क्यों महंगा हो रहा है डीजल-पेट्रोल

अहमदाबाद। एजेंसी

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने सोमवार को देश में पेट्रोल, डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के लिये वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम (Crude Oil Price) में आई तेजी को जिम्मेदार बताया। प्रधान ने माना कि हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल को माल एवं सेवाकर (GST) के दायरे में लाने के बारे में कोई भी निर्णय जीएसटी परिषद को लेना है। माना जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनके दाम में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा, ''पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच जाना है। इससे घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ गये जिसका उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ा है। भारत अपनी कुल जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है।''

डीजल-पेट्रोल को लाना होगा जीएसटी के दायरे में

पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने को लेकर संवाददाताओं द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रधान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वड़ोदरा स्थित के विस्तार को लेकर गुजरात सरकार और आईओसी के बीच आपसी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर गांधीनगर पहुंचे थे। जनता को ईंधन के बढ़ते दाम से राहत देने के लिये पेट्रोल, डीजल को जीएसटी व्यवस्था के दायरे में लाये जाने को लेकर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि वह इस विचार से सहमत हैं। उन्होंने कहा, ''पेट्रोल, डीजल के दाम वैश्विक बाजारों के अनुरूप चलते हैं। इस क्षेत्र प्रभारी होने के नाते मेरा यह मानना है कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिये लेकिन यह काम तभी हो पायेगा जब जीएसटी परिषद के सदस्यों के बीच इसको लेकर सहमति बनेगी। इस बारे में कोई भी निर्णय सामूहिक तौर पर जीएसटी परिषद ही ले सकती है।''

सोने की कीमत सुनकर दिल हो जाएगा खुश

बुधवार को भी दाम कम

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सोना खरीदने वालों के लिए फिर अच्छी खबर है। वायदा बाजार में लगातार तीसरे दिन

सोने की वायदा कीमत में गिरावट आई। बुधवार को एमसीएक्स पर सोना वायदा 49,159 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि चांदी वायदा 0.2 फीसदी बढ़कर 71,370 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 0.8 फीसदी गिरी थी। पिछले सप्ताह पांच माह के उच्च स्तर, 49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचने के बाद सोने में गिरावट आई है। हालांकि सोना पिछले साल अगस्त में अपने उच्चतम स्तर 56200 रुपये प्रति 10 ग्राम से करीब सात हजार रुपये सस्ता है। मार्च में सोने की कीमतें लगभग 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई थीं।

वैश्विक बाजार में इतनी है कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 0.1 फीसदी ऊपर 1,893.78 डॉलर प्रति औंस पर था। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 27.63 डॉलर प्रति औंस पर थी और प्लैटिनम 0.1 फीसदी गिरकर 1,160.81 डॉलर पर रहा। बीते वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सोने का आयात 22.58 फीसदी बढ़कर 34.6 अरब डॉलर या 2.54 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

सराफा बाजार में ये हैं दाम

दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 190 रुपये की तेजी के साथ 48,320 रुपये प्रति दस ग्राम (Gold price today) हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 125 रुपये बढ़कर 70,227 रुपये प्रति किलोग्राम (Silver price today) के भाव पर पहुंच गई। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70,102 रुपये प्रति किलोग्राम था।

कच्चे तेल में आई नरमी तो नही बदले दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका में इन दिनों कच्चे तेल का बड़ा भंडार जमा हो गया है। इनर्जी इंफोमेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि बीते 4 जून को समाप्त सप्ताह में वहां कच्चे तेल का भंडार 5.2 मिलियन बैरल पर था। उक्त सप्ताह के दौरान 3.57 मिलियन बैरल तेल के ड्रॉ का अनुमान था लेकिन 2.1 मिलियन बैरल का ड्रॉ हुआ। इस वजह से बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें टूट गई। भारत में देखें तो आज पेट्रोल-डीजल बाजार में कोई तब्दीली नहीं हुई। हालांकि, कल ही दोनों ईंधनों के दाम में 25-25 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली के बाजार में गुरुवार को पेट्रोल 95.56 रुपये प्रति लीटर पर जबकि डीजल 86.47 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।

22 दिनों में ही 5.24 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

ऐसा देखा गया है कि अपने यहां जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर-ठहर कर 22 दिनों में ही दिन में पेट्रोल 5.17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है।

22 दिन में 5.69 रुपये महंगा हुआ है डीजल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बीते 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अंतिम बार 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दो महीने से भी ज्यादा दिनों तक इसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चुनाव बीतने के बाद बीते 4 मई से अब तक रूक-रूक कर 22 दिनों में ही डीजल का दाम 5.69 रुपये प्रति लीटर चढ़ चुका है।

गेल के विभाजन की योजना रद्द, कंपनी पाइपलाइन कारोबार में इनविट के जरिये कुछ हिस्सेदारी बेचेगी

नई दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की गेल (इंडिया) लि. के विभाजन प्रस्ताव फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसकी जगह कंपनी इनविट के जरिये पाइपलाइन कारोबार में कुछ हिस्सेदारी बेचकर उसका मौद्रीकरण करेगी। गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी ने अपनी दो पाइपलाइन परियोजनाएं बाजार पर चढ़ाने को लेकर योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) चालू वित्त वर्ष में ही संभव है। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन और कारोबार करने वाली कंपनी है। देश में 17,126 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क में से करीब तीन चौथाई कंपनी के अधीन है। इससे गेल की बाजार में मजबूत स्थिति है। इसी को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया था कि गेल के पाइपलाइन कारोबार को अलग कंपनी का रूप दिया जाएगा। कंपनी के वित्तीय परिणाम के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में जैन ने कहा, ''इस संदर्भ में कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है।'' उनसे यह पूछा गया था कि कंपनी के पाइपलाइन कारोबार को नई अनुषंगी इकाई में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ। इस प्रस्ताव के तहत गेल के पास

प्राकृतिक गैस विपणन और पेट्रोरसायन उत्पादन का कारोबार रह जाता। उन्होंने कहा, ''हम शुरू में इनविट के जरिये पाइपलाइन कारोबार को बाजार में पेश कर रहे हैं। दो पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये इनविट को लेकर प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है। एक बार इसकी मंजूरी मिलने के बाद, हम इसे बाजार पर चढ़ाने की योजना पर आगे कदम बढ़ाएंगे।'' यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब है कि कंपनी की विभाजन योजना को रद्द कर दिया गया है, उन्होंने कहा, ''ऐसा ही जान पड़ता है।'' जैन ने कहा कि गेल अपनी कुछ पाइपलइन को बाजार पर चढ़ाएगी। इसके लिये इनविट के जरिये मामूली हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसके पीछे सोच यह है कि निरंतर आय सृजित करने वाले पाइपलाइन को न्यास को सौंपा जाए जो यूनिट निवेशकों को बेच सकता है और उसका शेयर बाजार में कारोबार हो सकता है। इसके जरिये गेल को तुरंत पैसे मिलेंगे जिसका उपयोग पूंजी व्यय में किया जा सकता है। इसकी शुरूआत गेल दाहेज-उरन-पनवेल-दाभोल पइपलाइन और दाभोल-बेंगलुरू-पाइपलाइन से कर सकती है। इनविट म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसके जरिये संभावित निवेशक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में छोटी राशि के जरिये निवेश कर नियमित आय के रूप में रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनविट के माध्यम से शुरू में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है। जैन के अनुसार मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। वहां से समय से मंजूरी के बाद इनविट चालू वित्त वर्ष में पेश किया जा सकता है।

जून के पहले हफ्ते में निर्यात 52.39 प्रतिशत बढ़कर 7.71 अरब डॉलर रहा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग तथा पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी मांग के चलते भारत का निर्यात इस महीने के पहले सप्ताह के दौरान 52.39 प्रतिशत बढ़कर 7.71 अरब डॉलर हो गया। आयात भी 1-7 जून के दौरान लगभग 83 प्रतिशत बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो गया।

आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इंजीनियरिंग का निर्यात 59.7 प्रतिशत बढ़कर 74.11 करोड़ अमरीकी डालर, रत्न और आभूषण का निर्यात 96.38 प्रतिशत बढ़कर 29.78 करोड़ अमरीकी डालर और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 69.53 प्रतिशत बढ़कर 53.06 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि में लौह अयस्क, तिलहन और मसालों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जून के पहले सप्ताह में पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात 135 प्रतिशत बढ़कर 1.09 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती तथा कीमती पत्थरों के आयात में भी बढ़ोतरी हुई। इस दौरान अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जबकि चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से आयात तेजी से बढ़ा।

इंडियन ऑयल का बड़ा प्लान

24 हजार करोड़ रुपयों के निवेश से शुरू करने जा रहा है ये 6 प्रोजेक्ट!

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने बड़ोदरा में कोयली रिफाइनरी में कच्चे तेल की प्रसंस्करण सुविधा की विस्तार योजना में पेट्रोरसायन और ल्यूब्रिकैंट इकाई को भी स्थापित करने की कुल 24 हजार करोड़ रुपये की निवेश योजना पर गुजरात सरकार के साथ हस्ताक्षर किये हैं। इस निवेश के साथ कंपनी 6 प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। इनमें पेट्रोकैमिकल्स के लिए ल्यूपक प्रोजेक्ट, दुमद में एक्रेलिक्स-ऑक्सो प्रोजेक्ट, जेआर और दुमद में KAhSPL के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, दुमद में LAB TTL सुविधा के शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट, जेआर में न्यू फ्लैर का प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन डिस्पैंसिंग फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

कंपनी ने सोमवार को विज्ञप्ति में कहा कि कोयली रिफाइनरी की क्षमता को 43 लाख टन लाख सालाना से बढ़ाकर 1.80 करोड़ टन सालाना किया जायेगा। इसके साथ ही इसमें पांच लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता की पोलीप्रापिलीन इकाई और 2.35 लाख टन क्षमता की ल्यूब्रिकैंट की मूल सामग्री बना का संयंत्र लगाया जायेगा।

धर्मेंद्र प्रधान और विजय रुपाणी रहे मौजूद

इस पूरे कार्य पर कुल 24,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इस निवेश परियोजना को लेकर गुजरात सरकार और इंडियन ऑयल के बीच आपसी सहमति के ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी और केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी उपस्थित थे। कंपनी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना के तैयार होने से कंपनी की पेट्रोरसायन के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर तैयारी मजबूत होगी। इससे कंपनी पीवीसी, स्टायरेन, एक्रिलोनिट्रायल, पालि मिथाइल मेथाक्रयलेट और एथलीन आक्साइड जैसे रसायनों के उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगी।

क्या बोले आईओसी के चेयरमैन?

आईओसी ने कहा कि इस अवसर पर कोयली- अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन के लिये दुमद में ढांचागत सुविधाओं को तैयार करने और साथ ही डिटरजेंट उद्योग के काम आने वाले लीनियर एल्काइल बेंजीन (एलएबी) के लिये टैंक- ट्रक लोडिंग सुविधा को भी तैयार करने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

आईओसी के चेयरमैन एस एम वैद्य ने इस अवसर पर कहा, ''गुजरात रिफाइनरी अब 1.80 करोड़ टन सालाना क्षमता तक पहुंचने की तैयारी में है। रिफाइनरी में अब पोलिप्रापिलीन, ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक और बुटायल एक्रीलेट की उत्पादन इकाइयां भी जुड़ जायेंगी।' वहां निर्माण से एक व्यक्ति के हिसाब से 12.5 करोड़ घंटे के काम के अवसर उत्पन्न होंगे।

गेल का मुनाफा चौथी तिमाही में 28 फीसदी बढ़ा, जानिए कितना हुआ कंपनी को फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी गैस कंपनी गेल ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में उसका कुल लाभ 28 फीसदी बढ़कर 1,907.67 करोड़ रुपये रहा। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोकेमिकल मार्जिन बढ़ना रहा। गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने पत्रकारों के साथ आनलाइन बातचीत में कहा कि जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में कंपनी का कुल मुनाफ़ा 1,907.67 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,487.33 करोड़ रूपए था।

उन्होंने कहा कि मुनाफा में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पेट्रोकेमिकल व्यवसाय का अच्छा प्रदर्शन और प्राकृतिक गैस विपणन और एलपीजी खंड रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण लगाए गए सख्त लॉकडाउन से निकलने के बाद पेट्रोकेमिकल संयंत्र पूरी क्षमता के साथ चले, जिससे कंपनी को पेट्रोरसायन कारोबार में कर पूर्व लाभ 40 प्रतिशत बढ़कर 608 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने बताया कि कीमतों में सुधार से गैस कारोबार में मजबूती लौटी, जिससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में इस कारोबार में 73.70 करोड़ रुपये के पिछले साल घाटे के मुकाबले इस वर्ष 281 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हुआ। उन्होंने कहा, ''वित्त वर्ष 2021 की पहली और दूसरी तिमाही कम कीमतों की वजह से काफी ख़राब रही। हमें बड़ा झटका लेकिन हम शेष वित्तीय वर्ष 2020-21 में घाटे की भरपाई करने में सफल रहे हैं। उम्मीद है वित्त 2021-22 अच्छा रहेगा।'' उन्होंने कहा, ''मौजूदा वित्त वर्ष में कच्चे तेल के 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिससे अच्छा मार्जिन प्राप्त होता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लागू प्रतिबंधों से अप्रैल और मई में गैस की खपत प्रभावित हुई है।'' वही, पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में गेल का लाभ 26 प्रतिशत घटकर 4,890 करोड़ रुपये रहा। इसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की पहली छमाही में लगा लॉकडाउन रहा। इस दौरान कंपनी का कारोबार भी 21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,529 करोड़ रुपए रह गया।

टैक्स कंप्लायंस बढ़ाएगा नया पोर्टल

आयकर विभाग की नई वेबसाइट में कई सुविधाएं

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग की कर रिटर्न के लिए नई वेबसाइट सोमवार रात को शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इसको लेकर कहा कि इससे कर अनुपालन बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने नया पोर्टल www.incometax.gov.in शुरू होने की घोषणा करते हुए कहा कि कर अनुपालन अनुभव को करदाताओं के और अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

ई-फाइलिंग के लिए नई वेबसाइट 2.0 के साथ टैक्स संबंधी मामलों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था है। इसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं जिससे करदाता घर बैठे यहां तक कि अपने मोबाइल से भी रिटर्न भर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि इस वेबसाइट के जरिए न सिर्फ करदाताओं की रिटर्न फाइलिंग आसान बनाई जाएगी बल्कि उनका रिफंड भी तेज किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ दी गई जानकारी के मुताबिक डेस्कटॉप पर पोर्टल के जरिए मिलने वाली सभी प्रमुख सेवाएं आयकर विभाग मोबाइल एप पर भी उपलब्ध कराया गया है।करदाताओं को भुगताान करने में आसानी हो इसके लिए वो किसी भी बैंक खाते से नेटबैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के इस्तेमाल भुगतान कर सकेंगे। आयकरदाताओं की सुविधा और मोबाइल के बढ़ते उपयोग को देखते हुए आयकर विभाग मोबाइल एप से टैक्स रिटर्न की सुविधा देने जा रहा है। ऐसा है नया पोर्टल: आयकर विभाग के मुताबिक पोर्टल का नाम ई-फाईलिंग 2.0 रखा गया है। नए पोर्टल के लिए http://incometax.gov.in लिंक पर क्लिक करना होगा।

पहले से भरा आईटीआर

आयकर विभाग के अनुसार नए पोर्टल को मोबाईल के जरिये इस्तेमाल करना आसान होगा। इस पर पहले से भरे आयकर विवरण, आईटीआर फॉर्म और सरल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही इस तरह की कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दी गई जानकारी में किसी तरह का अंतर आता है तभी आयकर विभाग दस्तावेज की मांग करेगा क्योंकि इसकी जरूरत पहले ही खत्म हो चुकी है।

ऐप बताएगा रिटर्न का तरीका

आयकर विभाग का कहना है कि इस नए पोर्टल में मोबाईल बेहद अहम होगा। विभाग का कहना है कि पोर्टल पर आयकरदाताओं को उपयोगकर्ता मैन्युअल और वीडियो क्लिप के जरिये हर कदम पर दिशा-निर्देश मिलेंगे यानी उसमें टैक्स रिटर्न भरने की तरीका बताया जाएगा।

भुगतान का विवरण तुरंत दिखेगा

पुरानी वेबसाइट में एनएसडीएल को जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें चालान जमा करने के बाद काफी बाद में भुगतान का विवरण दिखता था, लेकिन नई वेबसाइट में भुगतान के तुरंत बाद उसका विवरण दिखेगा। इसके अलावा सीबीडीटी एक नयी कर भुगतन प्रणाली भी 18 जून का शुरू करने जा रहा है।

सभी जरूरी जानकारी मिलेगी

करदाता की तरफ से किए गए सभी कामकाज का ब्योरा डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। इसमें विभाग की तरफ से हुए सभी तरह के संवाद और अपलोड किए गए दस्तावेज या फिर लंबित कामकाज की जानकारी रहेगी।

कॉल सेंटर की सुविधा

इस वेबसाइट पर आम तौर पर पूछे जाने वालों सवालों और उनके जवाबों (एफएंडक्यू) की सूची होगी। यही नहीं टैक्स से जुड़ी समाग्री, वीडियो और चैटबॉट भी मौजूद रहेगा जो करदाताओं की शंका का समाधान करेगा। इसके अलावा फिर भी कोई सवाल नहीं सुलझता है तो नए तैयार हुए कॉल सेंटर की मदद ली जा सकेगी।

Income Tax

PPF, NPS के अलावा इन पांच सोर्स भी कर मुक्त होते हैं, चेक करें डीटेल्स

नई दिल्ली। एजेंसी

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है। तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अपने हिस्से का कम से कम टैक्स देना पड़े इसलिए लोग एनपीएस, पीपीएफ, इपीएफ जैसे स्कीम में इनवेस्टमेंट करते हैं। इन सभी स्कीम में इनवेस्टमेंट के बदले टैक्सपेयर्स को अधिक छूट मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कई और कानूनी तरीके हैं जिसके जरिए टैक्सपेयर्स अपना पैसा बचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे तरीकों को मुंबई के टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं, 'अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये तक कोई गिफ्ट देता है तो उसे छूट मिलेगी। इसके अलावा प्रॉफिट पार्टनरशिप शेयर, पैतृक संपत्ति, ग्रेजुएटी और एजुकेशन स्कॉलरशिप पर भी इनकम टैक्स नियम 1961 के तहत कुछ छूट मिलती है।'

1- मैरिज गिफ्ट - टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं, 'अगर आपको शादी के लिए गिफ्ट मिलता है तो वह 100 प्रतिशत टैक्स कर मुक्त होगा। लेकिन यह गिफ्ट शादी के आसपास की तारीख को मिलना चाहिए। या फिर को सबूत दिया जाए जिससे साबित हो सके कि यह मैरिज गिफ्ट है। इसके अतिरिक्त 50 हजार रूपये के गिफ्ट तक टैक्स में छूट मिलता है।'

2- पार्टनरशिप फर्म से कमाया गया प्रॉफिट : बलवंत जैन कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म से कमाया गया प्रॉफिट भी पूरी तरह से कर मुक्त होता है क्योंकि कंपनी पहले से ही टैक्स दे चुकी होती है।

3- एजुकेशन स्कॉलरशिप: बलवंत जैन बताते हैं कि भारत या विदेशों से मिली एजुकेशन स्कॉलरशिप भी पूरी तरह से कर मुक्त होती है।

4- पैतृक संपत्ति: अपने पूर्वजों से पाई गई संपत्ति भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है।

5- ग्रेजुएटी : 20 लाख रुपये तक मिले ग्रेजुएटी भी 100 प्रतिशत टैक्स फ्री होती है।

इसके अलावा एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।

इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को लेकर इंफोसिस ने दी सफाई, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। एजेंसी

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने बुधवार को आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट की समस्याएं इस सप्ताह दूर होने और उसके सुचारू रूप से काम करने की उम्मीद जतायी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक दिन पहले इन्फोसिस से नई ई-फाइलिंग वेबसाइट में आ रही तकनीकी खामियों को लेकर कहे जाने के बाद कंपनी ने यह बात कही। उल्लेखनीय है कि सीतारमण ने मंगलवार को इन्फोसिस और उसके चेयरमैन नंदन निलेकणि से आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। ट्विटर पर भारी संख्या में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद वित्त मंत्री ने यह कदम उठाया।

इन्फोसिस ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा है, ''हमारी टीम तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिये काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह वेबसाइट सुचारू रूप से काम करने लगेगी। इन्फोसिस को 2019 में अगली पीढ़ी की आयकर फाइलिंग प्रणाली तैयार करने का अनुबंध दिया गया था। इसका मकसद रिटर्न की प्रसंस्करण प्रक्रिया में लगने वाले 63 दिन के समय को कम कर एक दिन करने और 'रिफंड प्रकिया को तेज करना है। वित्त मंत्री ने मंगलवार सुबह ट्विटर के जरिये आयकर फाइलिंग का नया पोर्टल शुरू किये जाने की घोषणा की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके ट्विटर टाइमलाइन पर उपयोगकर्ताओं की कई शिकायतें आने लगीं थीं। बाद में सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा, ''मैंने अपने टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं। उम्मीद है कि इन्फोसिस और नंदन निलेकणि प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता में हमारे करदाताओं को निराश नहीं करेंगे।'

बाद में, देर शाम सीतारमण के ट्वीट का जवाब देते हुए निलेकणि ने लिखा कि पहले दिन कुछ तकनीकी मसले आये हैं और इन्फोसिस उसके समाधान के लिये काम कर रही है।निलेकणि ने ट्विटर पर लिखा, ''नया ई-फाइलिंग पोर्टल कर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सुगम बनाएगा और उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। पहले दिन कुछ तकनीकी मसले आये हैं और इन्फोसिस उसके समाधन के लिये काम कर रही है। इन्फोसिस को तकनीकी खामियों को लेकर अफसोस है और सप्ताह के दौरान प्रणाली सुचारू हो जाएगी।'

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा

घाटे की भरपाई के लिए नोट छापना होता है आखिरी रास्ता!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से नोट की छपाई कर सरकार को जरूरी वित्त उपलब्ध करा सकता है लेकिन इसका उपयोग तभी होना चाहिए, जब कोई और उपाय न बचा हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी इस तरह की स्थिति नहीं है। सुब्बाराव ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिये राज्यों के स्तर पर लगाये गये 'लॉकडाउन' से अर्थव्यवस्था में नरमी आयी है। इससे निपटने के लिय सरकार पैसा जुटाने के लिये कोविड बांड लाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यह बजट में निर्धारित कर्ज के अतिरिक्त नहीं बल्कि उसी के अंतर्गत होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आरबीआई सीधे नोट की छपाई कर सकता है, लेकिन यह तभी होना चाहिए जब कोई और उपाय नहीं बचा हो। निश्चित रूप से, ऐसा भी समय होता है जब प्रतिकूल प्रभाव होने के बावजूद अतिरिक्त मुद्रा की छपाई जरूरी होती है। यह स्थिति तब होती है जब सरकार अपने घाटे का वित्त पोषण तार्किक दर पर नहीं कर सकती।'' सुब्बाराव ने कहा, ''बहरहाल, हम अभी वैसी स्थिति में नहीं हैं।''

जीडीपी में आई 7.3 फीसदी की गिरावट

देश की अर्थव्यवस्था में मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जो विभिन्न अनुमानों से कम है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसे 2025-26 तक कम कर 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

रिजर्व बैंक ने महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न अनिश्चितता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिये देश के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 10.5 प्रतिशत से कम कर 9.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं विश्व बैंक ने मंगलवार को 2021 में आर्थिक वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी है।

सुब्बाराव के अनुसार जब लोग कहते हैं कि आरबीआई को सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापना चाहिए, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि केंद्रीय बैंक घाटे को पूरा करने के लिए अब भी मुद्रा की छपाई कर रहा है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिये जब रिजर्व बैंक अपने खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के तहत बांड खरीदता है या अपने विदेशी मुद्रा संचालन के तहत डॉलर खरीदता है, तो वह उन खरीद के भुगतान के लिए मुद्रा की छपाई कर रहा है और यह पैसा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के कर्ज वित्त पोषण के लिए जाता है।

और क्या बोले सुब्बाराव?

सुब्बाराव ने कहा, ''हालांकि इसमें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जब आरबीआई अपने नकदी व्यवस्था के हिस्से के रूप में नोट छापता है, तो वह खुद चालक की सीट पर होता और यह तय करता है कि कितने नोट छापने हैं तथा उसे कैसे आगे बढ़ाना है।''

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत अतिरिक्त मुद्रा छपाई को सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसमें छापे जाने वाली राशि की मात्रा और समय आरबीआई की मौद्रिक नीति के बजाय सरकार की उधार आवश्यकता से तय होता है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा, ''इस स्थिति को आरबीआई का मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण नहीं रहने के तौर पर भी देखा जाता है। इससे आरबीआई और सरकार दोनों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। साथ ही इसका प्रतिकूल वृहत आर्थिक प्रभाव होता है।''

रिजर्व बेंक के राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण से तात्पर्य है कि केन्द्रीय बैंक सरकार के लिये उसके राजकोषीय घाटे की भरपाई के तहत आपात व्यय के लिये मुद्रा की छपाई करता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या कोविड बांड एक विकल्प है, जिसके जरिये सरकार कुछ उधार लेने पर विचार कर सकती है, सुब्बाराव ने कहा, ''यह कुछ अच्छा विकल्प है, जिसपर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह बजट में निर्धारित उधार के अलावा नहीं, बल्कि उसके एक हिस्से के रूप में होना चाहिए।''

दूसरे शब्दों में, सुब्बाराव ने कहा कि बाजार में उधार लेने के बजाय, सरकार लोगों को कोविड बांड जारी करके अपनी उधार आवश्यकताओं का एक हिस्सा इससे जुटा सकती है। उन्होंने कहा, ''इस प्रकार के कोविड बांड से मुद्रा आपूर्ति नहीं बढ़ेगी और आरबीआई के नकदी प्रबंधन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।''

यह पूछे जाने पर कि क्या आरबीआई सरकार के राजकोषीय दबाव को कम करने में मदद के लिए अधिक मुनाफा कमा सकता है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक एक वाणिज्यिक संस्थान नहीं है और लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि आर्थिक पुनरूद्धार के लिये आरबीआई और क्या कर सकता है, उन्होंने कहा कि एक साल पहले आयी महामारी की शुरूआत से ही आरबीआई तेजी से और नये-नये कदम उठाता आ रहा है। सुब्बाराव ने कहा, ''आने वाले समय में आरबीआई क्या कर सकता है, यह गवर्नर ने हाल में मौद्रिक नीति समीक्षा को लेकर अपने बयान में स्पष्ट किया है। उसमें कहा गया है कि नकदी का 'समान' वितरण हो। यानी सर्वाधिक दबाव वाले क्षेत्रों को कर्ज की सुविधा मिले।''

निर्यात, एथनॉल मिश्रण से चीनी मिलों के मार्जिन में एक प्रतिशत तक की होगी वृद्धिः रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

लगातार दूसरे सत्र में निर्यात बढ़ने तथा पेट्रोल सम्मिश्रण के लिए एथनॉल की आपूर्ति बढ़ने के कारण चालू वित्तवर्ष में एकीकृत चीनी मिलों के मुनाफे में 0.75 से लेकर एक प्रतिशत अंक वृद्धि की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। लगातार दूसरे चीनी सत्र (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी निर्यात बढ़ने, पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए एथनॉल आपूर्ति बढ़ने के साथ, चालू वित्तवर्ष में एकीकृत चीनी मिलों का परिचालन मुनाफा पौना से लेकर एक प्रतिशत अंक तक सुधर कर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। क्रिसिल रेटिंग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, सरकार द्वारा हाल ही में एथनॉल-पेट्रोल सम्मिश्रण लक्ष्य को 20 प्रतिशत करने की समयसीमा को दो साल पहले 2025 करने की घोषणा की गई है। इससे मध्यम अवधि में इस गति को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनाफे में सुधार और नियंत्रित कर्ज स्तर से चालू वित्त वर्ष में एकीकृत मिलों के कर्ज लेने की क्षमता मजबूत होगी। इसमें कहा गया है कि दूसरी ओर गैर-एकीकृत चीनी मिलों के लिए ऋण क्षमता का परिदृश्य काफी हद तक स्थिर रहेगा। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, ''एकीकृत चीनी मिलों की लाभप्रदता को चीनी निर्यात बढ़ने, लाभकारी कीमतों और लाभकारी एथनॉल का अनुपात बढ़ने का समर्थन मिलेगा। वहीं घरेलू चीनी बाजार में कम लाभप्रदता के प्रभाव को इससे पाटने में मदद मिलेगी। वैश्विक बाजार में सफेद चीनी के दाम घरेलू चीनी मूलय के मुकाबले अधिक है और पिछले छह माह के दौरान ये 14.3 प्रतिशत बढ़कर 33.6 रुपये किलो पर पहुंच गये हैं। निर्यात सहायता के बिना जून 2021 में यह दाम है। इस मौसम में चीनी की कमी के चलते वैश्विक बाजार में दाम ऊंचे बने रहने की संभावना है। ब्राजील और थाइलैंड में चीनी उत्पादन में कमी आई है। इससे घरेलू चीनी मिलों का चीनी निर्यात लक्ष्य 60 लाख टन से भी ऊपर जा सकता है। हालांकि घरेलू स्तर पर गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि से चीनी मिलों के मुनाफे पर हल्का असर पड़ सकता है। गन्ने का दाम तो बढ़ा है लेकिन चीनी के न्यूनतम मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है यह 31 रुपये प्रति किलो पर ही स्थिर है। ऐसे में एकीकृत चीनी मिलों के मुकाबले गैर-एकीकृत चीनी मिलों पर ज्यादा असर पड़ सकता है।

नीति आयोग के सीईओ ने की मुक्त व्यापार समझौते की वकालत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि भारत अगर स्वयं को मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से अलग रखता है, तो देश आगे बढ़ने के बड़े अवसरों को खो देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियों को संरक्षणवादी रुख अपनाने के बजाए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के 'ऑनलाइन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि एफटीए देशों से आयात की बाढ़ होने का भय सही रुख नहीं है। कांत ने कहा, ''आप पहले आकार और पैमाने के साथ विनिर्माण कीजिए, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनिए ताकि आप दुनिया के बाजार में प्रवेश कर सके। समस्या यह है कि विनिर्माण से जुड़ी भारतीय कंपनियां संरक्षणवाद में भरोसा करती हैं और उसे बढ़ावा देती हैं।'' उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने का साहस दिखाना होगा।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने कहा, ''आप चाहें या न चाहें, समय के साथ आप देखेंगे कि विभिन्न ब्लॉक (समूह) के बीच एफटीए होगा और यदि भारत इससे बाहर रहता है, तो हम बड़े अवसरों को भी खो देंगे।'' उन्होंने कहा, ''और इसलिए यह भारतीय कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे वास्तव में इस बात को समझें कि यूरोप के साथ एफटीए को बढ़ावा न देकर आप एक क्षेत्र में लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन हमारे कपड़ा निर्यात को वहां नुकसान होगा।'' कांत ने कहा कि जब तक भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं, उन्हें वैश्विक बाजारों का लाभ होगा। उन्होंने कहा, ''यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आपको घरेलू बाजार में जो मिलता है, वैश्विक बाजारों में उसका 5 गुना मूल्य मिलता है। भारतीय कंपनियों को निर्यात पर ध्यान देना चाहिए और वैश्विक बाजार में प्रवेश के लिए भारत को एक केंद्र के रूप में उपयोग करना चाहिए।'' उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) से जुड़े एक सवाल के जवाब में कांत ने कहा कि सरकार यह समझती है कि भारत में सब कुछ नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, ''प्रतिस्पर्धी लाभ का सिद्धांत है। हम जिस क्षेत्र में बेहतर हैं, हमें उसका विनिर्माण करना चाहिए। जहां हम अच्छे नहीं है, उस क्षेत्र में विनिर्माण नहीं करना चाहिए।''

सरकार ने इस साल एमएसपी पर 82,648 करोड़ रुपए में रिकॉर्ड 418.47 लाख टन गेहूं खरीदा

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने अप्रैल में शुरू हुए मौजूदा विपणन वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 418.47 लाख टन गेहूं खरीदा है जिसपर 82,648 करोड़ रुपए खर्च हुये हैं। नवंबर 2020 के अंत से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के विरोध के बीच गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हासिल की गई है। किसान संघ तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिये जाने की मांग कर रहे हैं। रबी विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है लेकिन अधिकांश खरीद जून में होती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2021-22 के चालू रबी चिपणन सत्र के तहत गेहूं की खरीद एमएसपी पर सुचारू रूप से अभी जारी है, जैसा कि पिछले सत्रों में भी किया गया था।' गेहूं की खरीद आठ जून तक 418.47 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 373.22 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। बयान में कहा गया कि लगभग 82,648.38 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर चल रहे खरीद अभियान से लगभग 46 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। खरीद पूरे 2020-21 विपणन वर्ष में हासिल किए गए 389.92 लाख टन के पिछले उच्च स्तर को पार कर गई है।सरकारी स्वामित्व वाली संस्था भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए प्रमुख एजेंसी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, केंद्र लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल की बिक्री दो-तीन रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर करता है। कोविड संकट के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराये जाने की भी घोषणा की गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के लिए 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय रेलवे को संचार और सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार के लिए 700 मेगाहट्र्ज बैंड में पांच मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। रेलवे ने एक बयान में कहा कि इस स्पेक्ट्रम के साथ भारतीय रेलवे अपने मार्ग पर 'एलटीई' आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान कर सकेगा। करीब 25,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। रेलवे अभी अपने संचार नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल

फाइबर पर निर्भर है, लेकिन नए स्पेक्ट्रम के आवंटित होने के बाद वह तेज रफ्तार वाले रेडियो का उपयोग कर सकेगा।

जावड़ेकर ने कहा कि इस आवंटन से रेलवे के संचार और सिग्नलिंग नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'कैबिनेट ने भारतीय रेल को स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा तथा सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहट्र्ज बैंड में पांच मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी, इस पर अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है, यह परियोजना अगले पांच वर्षों में पूरी होगी।' रेलवे ने अपने बयान में कहा कि इससे रेलवे के परिचालन और रखरखाव व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव आएगा। इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग कर अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने तथा सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि आधुनिक रेल नेटवर्क से परिवहन लागत कम होगी वहीं उच्च दक्षता प्राप्त होगी। साथ ही इससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को पूरा करने और रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की खातिर बहुराष्ट्रीय उद्योग आकर्षित होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे के अनुसार एलटीई (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) का मकसद परिचालन, सुरक्षा आदि के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद आवाज, वीडियो और आंकड़े संबंधी संचार सेवाएं मुहैया कराना है।

माल ढुलाई के लिये स्वच्छ परिवहन के उपयोग से 311 लाख करोड़ रुपये के ईंधन की होगी बचतः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में माल ढुलाई के स्वच्छ और लागत प्रभावी उपायों के जरिये 2020 से 2050 तक 311 लाख करोड़ रुपये के 'लॉजिस्टिक' ईंधन की बचत हो सकती है। नीति आयोग की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश इन उपायों से अगले तीन दशकों में संचयी रूप से 10 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी ला सकता है। आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) ने 'भारत में माल ढुलाई में तेजीः माल परिवहन के लिये स्वच्छ और लागत प्रभावी रूपरेखा' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि माल और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण आने वाले समय में माल परिवहन की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत 2020 से 2050 के बीच 311 लाख करोड़ रुपये के 'लॉजिस्टिक' ईंधन की बचत कर सकता है। साथ ही 2020 से 2050 के दौरान 10 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लायी जा सकती है।'' इसमें कहा गया है कि भारत में 2050 तक अपनी 'लॉजिस्टिक' लागत को जीडीपी के 4 प्रतिशत तक कम करने और नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) तथा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन को क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कम करने की क्षमता है। रिपोर्ट के अनुसार, ''आर्थिक विकास के लिये माल परिवहन आवश्यक है, यह उच्च 'लॉजिस्टिक' लागत से प्रभावित है और शहरों में बढ़ते सीओ2 उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।'' इसमें नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यापार मॉडल और बुनियादी ढांचे विकास से संबंधित माल ढुलाई क्षेत्र के लिए समाधान की रूपरेखा दी गई है। सिफारिशों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, इंटरमॉडल परिवहन (माल ढुलाई के लिये दो परिवहन साधनों का उपयोग) को बढ़ावा देना, नीतिगत उपाय और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पायलट परियोजनाएं और कड़े ईंधन मानकों को शामिल करना शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की माल ढुलाई गतिविधियां 2050 तक पांच गुना बढ़ने का अनुमान है और लगभग 40 करोड़ नागरिक शहरों में आएंगे, अतः प्रणाली में एक संपूर्ण बदलाव माल ढुलाई क्षेत्र के उत्थान में मदद कर सकता है।

मंत्रिमंडल ने नई निवेश नीति का लाभ आरएफसीएल को देने को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने बुधवार को संशोधित नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के तहत सब्सिडी लाभ रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) को भी देने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ''संशोधित नई निवेश नीति-2012 जिसे 2014 में लाया गया, के तहत सब्सिडी लाभ उन कारखानों को मिलेगा जिनका गठन 2019 तक हुआ है। लेकिन आरएफसीएल का गठन 2021 में हुआ और यह नीति अब इस पर भी लागू होगी।'' उन्होंने कहा कि नियमों के तहत जो यूरिया कारखाने 2019 तक गठित हुए हैं, वे ही संशोधित नई निवेश नीति के तहत सब्सिडी के लिये पात्र थे। इसके बावजूद, यह लाभ आरएफसीएल को दिया गया है जिसका गठन 2021 में हुआ। इसका कारण इससे अंततः किसानों को लाभ होगा। आरएफसीएल 12.70 लाख टन सालाना यूरिया का उत्पादन करेगी। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी और देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नई निवेश नीति, 2021 को सात अकटूबर, 2014 को संशोधित किया गया था।

आरएफसीएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की संयुक्त उद्यम है। आधिकारिक बयान के अनुसार कंपनी एफसीआईएल की पुरानी रामागुंडम इकाई को दोबारा चालू कर रही है। इसके तहत 6,165 करोड़ रुपये की लागत से एक नया गैस आधारित नीम-कोटेड यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है। रामागुंडम संयंत्र के शुरू हो जाने से देश में यूरिया के घरेलू उत्पादन में 12.7 लाख टन सालाना का इजाफा होगा। इसके जरिये यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी। यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में एक होगी।

मध्य प्रदेश की समस्त न्यायालयों हेतु (टीकाकरण प्रमाण पत्र) वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उपरांत पहले परिसरों में प्रवेश की अनिवार्यता की मांग

सामाजिक संस्था न्यायाश्रय ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को किया ईमेल

इंदौर। विधि के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था न्यायाश्रय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल प्रेषित कर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के उपरांत ही पक्षकारों को न्यायालय परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने हेतु सर्कुलर जारी किए जाने की मांग की है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट पंकज वाधवानी ने प्रेषित मेल में कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते हमारी न्यायिक व्यवस्था अत्यंत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है और इस कोरोना संक्रमण से अनेक विद्वान न्यायाधीश गण, न्यायालय के कर्मचारी गण, विद्वान अधिवक्तागण इत्यादि अपना जीवन गंवा बैठे हैं, जिसकी अपूरणीय क्षति हमारे न्यायिक परिवार को हुई है संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए व्यापक स्तर पर दलदल है अथवा किन्हीं अन्य कारणों की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं । कहीं ना कहीं समाज के यही वर्ग किसी न किसी न्यायिक मुकदमे में पक्षकार भी हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय से यह अनुरोध है कि ऐसा सर्कुलर आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त न्यायालयों में परिसर में दाखिल होने के पूर्व वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण प्रमाण पत्र होने के उपरांत ही प्रवेश दिया जा सके। इस प्रकार के सर्कुलर से अनेक सामाजिक लाभ होंगे जैसे अनिवार्य वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और कोरोनावायरस का खतरा कम होगा।

IBC: बैंक लोन वसूली के लिए आये नए कानून से मिला है कितना फायदा?

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी (Covid Crisis) की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आई मुश्किलों को देखते हुए आईबीसी (IBC) के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया गया था। इसके तहत 25 मार्च, 2020 से एक साल के लिए आईबीसी के तहत कोई नया मामला शुरू करने की रोक थी। ये राहत अब खत्म हो गई है।

बहुत मामूली रिकवरी

देश में दिवालियापन कानून (IBC) आने के बाद बैड लोन लोन रिजोल्यूशन के मामले चिंताजनक स्तर पर बने हुए हैं। दिवालिया होने वाली कंपनियों से बैंक लोन की रिकवरी का रेट 24 फ़ीसदी पर सिमट गया है। सरकार कंपनियों से बैंक लोन (Bank Loan) की रिकवरी और उनके पुनर्वास की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। बैड लोन (Bad Loan) रिकवरी के लिए पुरानी मशीनरी में भी बैंक लोन के नुकसान का मामला 70 फ़ीसदी के करीब था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या आईबीसी (IBC) लागू होने के बाद सिर्फ 8 फ़ीसदी कंपनियों ने रिजोल्यूशन का विकल्प अपनाया है जबकि 30 फ़ीसदी कंपनियां लिक्विडेशन के लिए चली गई हैं।

बैंक की दिक्कत

विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लेटेस्ट ट्रेंड एवं प्रोग्रेस बैंकिंग रिपोर्ट से यह समझ आता है कि आईबीसी (IBC) के प्रावधानों के तहत रिकवरी रेट -45% हो गया है। लोन रिकवरी के लिए अन्य समाधान के तरीके 25 फ़ीसदी तक कारगर साबित हो रहे थे। आईबीबीआई (IBBI) के आंकड़े बताते हैं कि बैंक लोन रिकवरी रेट शीर्ष 9 अकाउंट की वजह से गिर रहे हैं। इसकी वजह से रिकवरी रेट - 24 फ़ीसदी हो गया है। इन 9 बड़े लोन अकाउंट में बड़ी स्टील कंपनियां शामिल हैं, जहां रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही है। पावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जहां कॉन्प्लेक्स एसेट हैं, वहां उनकी संपत्ति खरीदने के लिए बहुत कम कंपनियां आगे आ रही हैं।

बैंकरप्सी कोर्ट में बढ़े मामले

वित्त वर्ष 2017 से दिवालियापन कोर्ट (bankruptcy court) में 4300 मामले सुनवाई के लिए स्वीकार किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 8 फ़ीसदी का समाधान निकाला जा चुका है। इन मामलों में से 40 फ़ीसदी से ज्यादा अभी तक पेंडिंग है।बैंकरप्सी कोर्ट (bankruptcy court) में

आए मामलों में से 30 फीसदी में लिक्विडेशन का तरीका ढूंढा जा रहा है। कोरोना संकट (Covid crisis) की वजह से आर्थिक गतिविधियां मंद हुई हैं और दबाव वाली संपत्तियों के समाधान प्रक्रिया में और दिक्कत आने की आशंका है।

रियलाइजेशन प्लान में दिक्कत

पिछले साल की तुलना में इस साल कर्ज देने वाले संस्थानों का दिवालिया कंपनी से रियलाइजेशन प्लान कम हुआ है। इस साल सिर्फ 26,000 करोड रुपये के रियलाइजेशन प्लानसामने आए हैं यह साल 2020 की तुलना में एक चौथाई है। रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि कर्ज देने वाले संस्थान वित्त वर्ष 2022 में ?60,000 करोड़ का रियलाइजेशन प्लान ला सकते हैं। आईबीसी (IBC) के तहत सक्सेसफुल रियलाइजेशन प्लानके बाद इस रकम का अनुमान लगाया गया है। कर्ज देने वाले संस्थानों के रिलेशन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि दिवालिया कंपनियों में से आठ नौ बड़े कर्ज धारक का रियलाइजेशन प्लान किस हिसाब से किया जाता है।

क्या बारिश के पानी से कर्ज उतारा जा सकता है?

1. कहते हैं कि यदि कर्ज नहीं उतर पा रहा है तो बारिश का पानी एक बाल्टी में एकत्रित कर लें और उसमें दूध डालकर भगवान स्मरण करके पूरे माह में इसी तरह स्नान कर लें। ऐसा करने से धीरे-धीरे आपका कर्ज उतरने लगेगा।
2. यह भी कहा जाता है कि यदि कारोबार में घाटा हो रहा हो तो पीतल के बर्तन में वर्षा जल एकत्रित करके माता लक्ष्मी और विष्णुजी का एकादशी के दिन इस जल से अभिषेक करें। इससे व्यापारिक घाटा नहीं होगा और अच्छी इनकम होने लगेगी
3. मान्यता अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो मिट्टी के घड़े को बारिश के पानी से भरकर उसे घर की ईशान या उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है।
4. यह भी कहा जाता है कि एक कटोरी में बारिश का पानी भरकर छत पर रखकर जब उस पानी को अच्छे से धूप लग जाए तो उस पानी को अपने ईष?टदेव का नाम लेकर आम के पत्तों पर छिड़क दें। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की कमी दूर कर देती हैं।
5. यदि किसी को विवाह में परेशानी आ रही है तो वह बारिश का पानी एकत्रित करके भगवान गणेशजी का जलाभिषेक करें।
6. यदि किसी भी प्रकार का रोग है या कोई संकट है तो तो बारिश का पानी एकत्रित करके महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
7. यदि आपको लगता है कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जिसके कारण कर्ज आदि जैसी परेशानी हो रही है तो किसी बर्तन में बारिश का पानी एकत्रित करके उसे हनुमानजी के सामने रख दें और पूरे महीने प्रतिदिन 51 हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस पानी से घर के सभी हिस्सों में छिड़काव कर दें। इससे नकारात्मक शक्तियां हट जाएंगी।

नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चम्??

शनि जयंती
2021

शनिदेव को समझने में ही छुपा है समाधान

हिन्दू परंपरा में भगवान शनिदेव की पूजा का प्रचलन है। शनिदेव के संबंध में हमें पुराणों में कई कथाएं और कहानियां मिलती है। थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ ही लगभग सभी कथाओं में समानताएं हैं। इस बार शनि जयंती ज्येष्ठ माह की अमावस्या अर्थात 10 जून 2021 गुरुवार को है। आओ जानते हैं भगवान शनिदेव के संबंध में 10 रोचक बातें।

शनिदेव का जन्म

एक कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंदपुराण के काशीखंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम

छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछेक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है।

संज्ञा की छाया के पुत्र

सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना का जन्म हुआ और फिर संज्ञा ने ही सूर्यदेव के ताप से बचने के लिए संज्ञान ने अपने तप से अपना प्रतिरूप संवर्णा को पैदा किया और संज्ञा ने संवर्णा से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। संज्ञा उसे सूर्यदेव के महल में छोड़कर चली गई। सूर्यदेव ने उसे ही संज्ञा समझा और सूर्यदेव और संवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा (तपती) तीन संतानों ने जन्म लिया।। संज्ञा का प्रतिरूप होंने के कारण संवर्णा का एक नाम छाया भी हुआ।

छाया के तप से शनिदेव हुए काले

कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख-प्यास, धूप-गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानि शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया।

पिता और पुत्र में हुआ मनमुटाव

मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का अहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया।

शनिदेव का स्वरूप

शनिदेव के सिर पर स्वर्णमुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनीलमणि के समान। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। कहीं-कहीं इन्हें कौवे या भैंसे पर सवार भी बताया गया है। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। इन्हें यमाग्रज, छायात्मज, नीलकाय, क्रुर कुशांग, कपिलाक्ष, अकैसुबन, असितसौरी और पंगु इत्यादि नामों से जाना जाता है।

शनिदेव को पत्नी से मिला श्राप

ब्रह्मपुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया था। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंचीं, पर ये श्रीकृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे, वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतीकार की शक्ति उसमें न थी, तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो।

शनि की दृष्टी

कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टी एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल-जंगल भटकना पड़ा और एक बार तो उन्हें हाथी बनकर भी रहना पड़ा था। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। मात्र हनुमानजी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कभी कोई असर नहीं होता और वे अपने भक्तों को भी उनके असर से बचा लेते हैं।

श्रीकृष्ण और शनिदेव

जनश्रुति कथा के अनुसार मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था तब स्वर्ग से सभी देवताओं के साथ शनिदेव भी कृष्ण के बाल रूप को देखने मथुरा आए थे। नंदबाबा को जब यह पता चला तो उन्होंने भयवश शनिदेव को दर्शन कराने से मना कर दिया। नन्द बाबा को लगा कि शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही कहीं कृष्ण के साथ कुछ अमंगल न हो जाए। तब मानसिक रूप से शनिदेव ने भगवान श्रीकृष्ण से दर्शन देने की विनती की तो कृष्ण ने शनिदेव को कहा कि वे नंदगांव के पास के वन में जाकर तपस्या करें, वहीं मैं उन्हें दर्शन दूंगा। बाद में शनिदेव की तपस्या से भगवान श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कोयल के रूप में उन्होंने शनिदेव को दर्शन दिया।

हनुमान भक्त पर शनिदेव की कृपा

एक बार रामजप में बाधा डालने के बारण शनिदेव को हनुमानजी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना रामकार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटे आई। बाद में जब हनुमानजी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का अहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद में रामकार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुनामजनी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा और उन पर कृपा बनाए रखूंगा।

शनिदेव के सिद्धपीठ

शनि शिंगणापुर : महाराष्ट्र के शिंगणापुर में स्थित है शनिदेव का चमत्कारिक स्थान। कहते हैं कि यहीं पर शनिदेवजी का जन्म हुआ था। 2. शनिश्चरा मन्दिर : मध्यप्रदेश के ग्वालियर के पास स्थित है शनिश्चरा मन्दिर। इसके बारे में किंवदंती है कि यहाँ हनुमानजी के द्वारा लंका से फेंका हुआ अलौकिक शनिदेव का पिण्ड है। 3. सिद्ध शनिदेव : उत्तरप्रदेश के कोशी से छह किलोमीटर दूर कौकिला वन में स्थित है सिद्ध शनिदेव का मन्दिर। यहां शनिदेवजी कठोर तप करके श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे।

कर्म होता संचालित

शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता तथा राज्य का भाव माना गया है। एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। अतः शनि से बचने का एक मात्र तरीका अपने कर्म को शुद्ध रखना।

शनिदेव के प्रकोप से बचने के उपाय

1. प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े।
2. भगवान भैरव को कच्चा दूध या शराब चढ़ाएं।
3. छाया दान करें।
4. कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलावें।
5. अंधे-अपंगों, सेवकों और सफाईकर्मियों की सेवा करें।
6. तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ, और जूता दान देना चाहिए।

सूर्य ग्रहण के दिन ही शनि जयंती का बन रहा संयोग

साल का पहला सूर्यग्रहण 10 जून को मिलने वाला है और आपसे मिलने वाला भी ऐसा है। डिवाइस के सही होने की तारीख की स्थापना के समय सूर्य की तारीख की तारीख तय हो गई थी। ऐसे में सूर्य के प्रकाश के लिए सूर्य के प्रकाश पर संपूर्ण विधि-व्यवस्था से शनि देव की पूजा-क्रंच की स्थिति है तो शुभ फल। सूर्य का वैज्ञानिक विज्ञान उपयोगी होने के साथ-साथ उपयोगी भी है। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य के सूर्य के शनि देव कुछ राशियों पर मेहरबान हो सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में सुखी व्यक्ति जैसा व्यक्ति जैसा व्यक्ति होता है। सूर्य के प्रकाश की घटना से प्रकाश की उम्मीद है। शनि देव इस वर्ष राशि पर महरबान हैं। शनि जुबली का व्यक्ति वृष राशि के लिए बीमित व्यक्ति हो सकता है। जातक के परिवार के यादगार पल। अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की स्थिति में यह मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र से हानिकारक व्यक्ति भी ये खराब हो सकते हैं। शनि देव वृष राशि के लोगों के कार्य के परीक्षण विफल होंगे। वृश्चिक राशि पर शनि देव की विशेष स्थिति। शनि ग्रह का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ है। कामयाबी में सफल हो सकता है। जीवन में आनंद का अनुभव और लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्त होने की उम्मीद है। भाग्योदय हो सकता है। मीन राशि के जातकों का भी यह विशेष रूप से दृश्य है। गोकू सन की विशेष कृपा बन सकता है। सूर्य के प्रकाश प्रकाश प्रकाश जैसे हो सकता है। इस समय शुभ हो सकता है। समस्या से संबंधित है। सफल हो सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़कर 1,940 रुपये प्रति क्विन्टल हुआ

बाजारा में 100 रुपये बढ़े

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने बुधवार को फसल वर्ष 2021-22 के दौरान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही खरीफ मौसम की अन्य फसलों के एमएसपी भी बढ़ाये गये हैं। धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है, जिसकी बुवाई दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत आने के साथ शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने जून-सितंबर अवधि में मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे किसानों को खरीफ मौसम में फसल की बुवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमएसपी की घोषणा और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ खरीफ मौसम की बुवाई भी आगे बढ़ती है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से एमएसपी के बारे में आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, ''एमएसपी (फसलों पर) जारी है, इसे बढ़ाया जा रहा है और भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) के लिए धान (सामान्य किस्म) के एमएसपी को एक साल पहले के 1,868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इसी तरह, बाजरा का एमएसपी चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष के 2,150 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी को नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है और इसका लाभ किसानों तक पहुंच रहा है।

अब मिलेगा शुद्ध सरसों का तेल, मिलावट पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। एजेंसी

अब सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट नहीं की सकती। आपको बाजार में भी शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। विभिन्न स्रोत वाले तेलों से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल (एमएसईवीओ) के उत्पादन व पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक मंगलवार से प्रभावी हो गई है। सरकार की ओर से सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया था।

इसके अनुसार एमएसईवीओ के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति अथवा मंजूरी दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। इसके अनुसार अब सरसों तेल को दूसरे स्रोत के खाद्य तेलों के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत आने वाले विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

ने मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के सभी पैकिंग करने वालों के नयी दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम जारी इस आदेश में कहा गया है कि ' बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन में सरसों तेल के निषेध और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश क्रमशः आठ जून 2021 और एक जुलाई 2021 से अमल में आ जायेगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आठ मार्च 2021 के और एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति के 29 दिसंबर 2020 के सर्कुलर को सलंग्न करते हुये कहा गया है कि इस अधिसूचना में अब तक मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के तौर पर जाने जाने वाले बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि एगमार्क के तहत आने वाली जिंसों को एफएसएसएआई नियमों के अनुपालन की आवश्यकता होती है इसलिये मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल (बीईवीओ) के ग्रेडिंग और मार्केटिंग नियम एफएसएसएआई की अधिसूचना के अनुरूप संशोधित माने जाएंगे।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ रुपये आवंटित

नयी दिल्ली। एजेंसी

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तहत सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत दो लाख से अधिक गांवों की मदद के लिए 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गयी है। जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में बताया। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जबकि राज्य 8,300 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तथा शेष राशि अन्य स्रोतों से आयेगी। जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने एसडब्ल्यूबी (जी) की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा, ''स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण-दो का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में 40,700 करोड़ रुपये के निवेश से सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था के जरिये दो लाख से अधिक गांवों की मदद करना है।'' मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एमबीएम-जी की राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा, ''केंद्र करीब 14,000 करोड़ रुपये की मदद करेगा, राज्य 8,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेंगे। करीब 12,730 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे और 4,100 करोड़ रुपये मनरेगा से आयेंगे।'' इसके अलावा राज्य 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्य उद्योग मॉडल, सीएसआर और जैसी अन्य योजनाओं के जरिये निवेश करेंगे।

ऊर्जा दक्षता योजना पैट से 1.7 करोड़ टन सालाना तेल समतुल्य ऊर्जा की बचत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ऊर्जा दक्षता से जुड़ी पैट (परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड) योजना के जरिये 1.7 करोड़ टन तेल समतुल्य ऊर्जा बचत के साथ सालाना 8.7 करोड़ टन कार्बन (सीओ2) उत्सर्जन में कमी आयी है। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम उपकरणों के लिये स्टार लेबलिंग योजना के जरिये 2020-21 में 56 अरब यूनिट बिजली की बचत हुई है। रुपये के हिसाब से यह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैट योजना से फिलहाल करीब 1.7 करोड़ टन तेल समतुल्य ऊर्जा की बचत तथा 8.7 करोड़ टन सालाना सीओ2 उत्सर्जन में कमी आयी है।

बयान के अनुसार 2020 तक योजना के दायरे में 13 क्षेत्रों को लाया गया। ये वे क्षेत्र हैं, जहां ऊर्जा की खपत सर्वाधिक होती है। इसमें सीमेंट, लोहा और इस्पात, उर्वरक तापीय बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन, रेलवे तथा अन्य शामिल हैं। बिजली मंत्रालय अपने अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से उद्योगों, प्रतिष्ठानों और उपकरणों/इलेक्ट्रिक सामानों में बिजली बचत के उपायों के जरिये कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपाय कर रहा है। इस संबंध में, पैट योजना बड़े उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत, लक्षित बड़ी इकाइयों को ऊर्जा बचत के लिये अनिवार्य लक्ष्य दिया जाता है। अतिरिक्त ऊर्जा बचत होने पर उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसका कारोबार होता है। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता बढ़ावा देने के लिये चलाये जा रहे स्टैन्डर्ड एंड लेबिलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम के जरिये 2020-21 में 56 अरब यूनिट बिजली की बचत हुई है। रुपये के हिसाब से यह 30,000 करोड़ रुपये की बचत है। इतना ही नहीं इस योजना से हर साल करीब 4.6 करोड़ टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी हो रही है। बयान के अनुसार मार्च 2021 तक योजना के दायरे में 28 उत्पाद शामिल हो चुके हैं। इसके तहत उपकरणों में बिजली खपत के आधार पर एक से पांच स्टार दिये जाते हैं। इससे ग्राहकों को पता चलता है कि संबंधित उपकरण कितनी बिजली की बचत करेगा।

वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 2021-22 के दौरान 23-28% तक वृद्धि का अनुमानः क्रिसिल

मुंबई। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 23-28 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है, जबकि पहले 32-37 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की उम्मीद थी। क्रिसिल ने सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा कि इस बढ़ोतरी के बावजूद कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 2019 की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 30 प्रतिशत कम रह सकती है।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए पिछले साल लगाए गए सख्त लॉकडाउन के दौरान बिक्री दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 21 प्रतिशत घटकर 5,68,559 इकाई रह गई थी, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 7,17,539 था।

क्रिसिल ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन खंड में 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः 29 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की गिरावट हुई। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अप्रैल में भाड़े की दरों में करीब 20 प्रतिशत तक की गिरावट हुई और मई में मुनाफे को लेकर परिचालन में दबाव बना रहा।

पावर ग्रिड ने देश की पहली वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर आधारित एचवीडीसी प्रणाली चालू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने देश की पहली वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर (वीएससी) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) ट्रांसमिशन प्रणाली चालू की है। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इससे देश के दक्षिणी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी। बयान के अनुसार पावरग्रिड ने + +320 केवी, 2000 मेगावाट (एमडब्ल्यू), पुगलूर (तमिलनाडु) -त्रिचूर (केरल) वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर आधारित एचवीडीसी सिस्टम के मोनोपोल-1 को मंगलवार को चालू कर दिया। पुगलूर-त्रिचूर एचवीडीसी सिस्टम पर 5,070 करोड़ रुपये की लागत आयी है। यह रायगढ़-पुगलूर-त्रिचूर 6000 मेगावाट एचवीडीसी सिस्टम का हिस्सा है। यह त्रिचूर स्थित वीएससी एचवीडीसी स्टेशन के माध्यम से केरल को 2000 मेगावाट बिजली भेजने में काम आएगी। पावरग्रिड ने इस परियोजना के लिए पहली बार इस अत्याधुनिक वीएससी तकनीक का उपयोग किया है। वीएससी तकनीक से पारम्परिक एचवीडीसी प्रणाली की तुलना में भूमि की आवश्यकता खासी घट जाती है और यह ऐसे क्षेत्रों के लिए खासा अनुकूल है, जहां जमीन की कमी है। यह स्मार्ट ग्रिड के विकास को भी सुगम बनाता है। इस परियोजना की एक खास विशेषता ओवरहेड लाइन और अंडग्राउंड केबिल का संयोजन है, जो केरल में पारेषण कॉरिडोर की सीमित उपलब्धता का हल निकालती है।

देश में अनुसंधान, विकास आधारित दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरतः डीओटी अधिकारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में केवल कलपुर्जो को जोड़ने पर आधारित उत्पादन के बजाए अनुसंधान एवं विकास आधारित उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सदस्य (प्रौद्योगिकी) टी के पॉल ने बुधवार को यह कहा। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार उपकरण और इंटीग्रेटेड सर्किट तथा कल-पुर्जो में भारत का योगदान क्रमशः केवल 0.15 प्रतिशत और 0.068 प्रतिशत है। पॉल ने कहा कि यह स्थिति दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये डिजाइन आधारित विनिर्माण का आह्वान करता है।

उन्होंने ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के कार्यक्रम में कहा, ''...केवल एसेंबली आधारित विनिर्माण के बजाय अनुसंधान एवं विकास की क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।'' पॉल ने कहा, ''वर्तमान में देश में दूरसंचार उपकरणों की 85 प्रतिशत मांग आयात के जरिये पूरी की जाती है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है।'' उन्होंने कहा, ''इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति की तुलना में बढ़ी हुई मांग के कारण उपकरणों की लागत बढ़ गई है। यह हमारे लिए विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने का सही समय है।'' पॉल ने कहा, ''दूरसंचार विनिर्माण में आत्मनिर्भरता समय की जरूरत है।''

विश्वबैंक ने 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान को घटाया

वाशिंगटन। एजेंसी

विश्वबैंक ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर अनुमान को पहले जताये गये 10.1 प्रतिशत से घटाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया। उसने कहा है कि कोविड-19 महामारी की अबतक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरूद्धार को नुकसान पहुंचा है। कर्ज देने वाला बहुपक्षीय संस्थान ने 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। विश्वबैंक ने ग्लोबल इकोनामिक प्रॉस्पेक्ट्स (वैश्विक आर्थिक संभावनाएं) शीर्षक रपट के नए संस्करण में कहा है कि भारत में 2020-21 की दूसरी छमाही में खासकर सेवा क्षेत्र में तीव्र पुनरूद्धार देखा जा रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्थान के अनुसार, ''महामारी की शुरूआत से किसी भी देश के मुकाबले सर्वाधिक भीषण लहर भारत में आयी और इससे आर्थिक पुनरूद्धार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में अबतक की सबसे खराब 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि 2019-20 में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विश्वबैंक ने इस साल अप्रैल में 2021-22 में जीडीपी में 10.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया था। यह जनवरी में जताये गये 5.4 प्रतिशत वृद्धि से अधिक था। लेकिन अब अनुमान को कम कर दिया गया है। बहुपक्षीय संस्थान ने 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। विश्वबैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में 5.6 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। अगर ऐसा होता तो है कि यह 80 साल में मंदी के बाद की यह सबसे मजबूत वृद्धि होगी।

इसमें कहा गया है, ''भारत की जीडीपी में 2021-22 (अप्रैल-मार्च) में 8.3 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय समेत नीतिगत समर्थन तथा सेवा एवं विनिर्माण में अपेक्षा से अधिक पुनरूद्धार से गतिविधियों में तेजी आएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमान में कोविड-19 की दूसरी लहर तथा इसकी रोकथाम के लिये मार्च 2021 से स्थानी स्तर लगायी पाबंदियों के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान पर गौर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''महामारी से खपत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भरोसा पहले से कमजोर बना हुआ है और बही-खातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर धीमी पड़कर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह कोविड-19 के परिवार, कंपनियों तथा बैंकों के बही-खातों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव, ग्राहकों का भरोसा कमजोर होना तथा रोजगार एवं आय के मामले में अनिश्चितता को अभिव्यक्त करता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में इसमें 5.6 प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता तो है कि यह 80 साल में मंदी के बाद मजबूत वृद्धि होगी। इसका मुख्य कारण कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत पुनरूद्धार है। हालांकि पुनरूद्धार के बावजूद वैश्विक उत्पादन महामारी पूर्व अनुमान के मुकाबले इस साल 2 प्रतिशत कम रहेगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका में इस साल 6.8 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया है। इसका कारण बड़े स्तर पर राजकोषीय मदद तथा महामारी से जुड़ी पाबंदियों में ढील है। अन्य विकसित देशों में वृद्धि मजबूत होगी लेकिन उसकी गति कम होगी।

रिपोर्ट के अनुसार उभरते और विकासशील देशों में चीन की वृद्धि दर 2021 में 8.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। इसकी वजह दबी हुई मांग में तेजी आना है। विश्वबैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा, ''वैश्विक स्तर पर पुनरूद्धार के संकेत हैं लेकिन महामारी के कारण विकासशील देशों में गरीबी और असमानता बढ़ी है।' उन्होंने कहा, 'वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए टीका वितरण और ऋण राहत में तेजी लाने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। स्वास्थ्य संकट कम होने के साथ नीति निर्माताओं को महामारी के स्थायी प्रभावों को दूर करने और व्यापक तौर पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए हरित, मजबूत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होगी।'

भारत ने कोविड-19 का मुकाबला अच्छे से किया लेकिन दूसरी लहर में चोट खाईः विश्वबैंक अध्यक्ष

वाशिंगटन। एजेंसी

भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ''काफी मुश्किल'' बताते हुये विश्वबैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने मंगलवार को कहा कि महामारी की दूसरी लहर से गहरी चोट खाने से पहले भारत ने कोविड- 19 से मुकाबले में अच्छी प्रगति कर ली थी। भारत ने अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से मुकाबला किया। इस दौरान रोजाना तीन लाख से अधिक नये मामले सामने आ रहे थे। अस्पतालों में बिस्तरे उपलब्ध नहीं थे। चिकित्सा आक्सजीन की भी कमी हो गई थी। एक समय मध्य मई में कोरोना वायरस के नये मामले चार लाख के भी पार निकल गये थे।

मालपास ने वैश्विक आर्थिक संभावना पर ताजा रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर संवाददाताओं के साथ कन्फ्रेंस कॉल में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, ''यह भारत के लिये बहुत कठिन स्थिति है। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में प्रगति हासिल की थी और उसके बाद उसे बहुत बहुत बड़ी दूसरी लहर का सामाना करना पड़ा जिसकी वजह से कई मौतें हुई और फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।''

एक सवाल के जवाब में मालपास ने कहा, ''हम जान जाने पर शोक प्रकट करते हैं। भारत को गहरी चोट पहुंची है। जहां तक अर्थव्यवसथा को फिर से पटरी पर लाने की बात है, भारत के पास उसकी खुद की बड़ी टीका उत्पादन क्षमता है, उसका खुद का उत्पादन है। उसे तेजी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका नये मामलों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा और मुझे लगता है इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है।'' विश्वबैंक संभावना समूह के निदेशक अयान कोसे ने कहा कि रिपोर्ट में 2021 में भारत की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। हमारे जनवरी के अनुमान के मुकाबले वास्तव में यह (2.9 प्रतिशत) बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 की बड़ी लहर से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार काफी मजबूत था।

अरब-भारत ऊर्जा मंच के पहले संस्करण में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर हुई चर्चा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत-अरब ऊर्जा मंच के बुधवार को संपन्न पहले संस्करण में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में बिजली व्यापार को बढ़ावा देने के विभिन्न तौर तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत और मोरक्को किंगडम की सह-अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह, मोरक्को के ऊर्जा और खान मंत्री अजीज रब्बा और अरब लीग के आर्थिक मामलों के सहायक महासचिव कमल हसन अली ने संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ''ऊर्जा पारगमन, अंतर-क्षेत्रीय बिजली व्यापार, हाइड्रोकार्बन और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई।'' उसने कहा, ''इस दौरान विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के क्षेत्र में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम व्यवहारों का आदान-प्रदान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का त्वरित विकास और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उत्पादन समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई।''

मास्टर प्लान में दिल्ली को 24 घंटे आर्थिक गतिविधियों वाला शहर बनाने पर जोर

नयी दिल्ली। दिल्ली के 2041 के मास्टर प्लान मसौदे में राज्य में 24 घंटे आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के साथ ही कनॉट प्लेस सहित अन्य वाणिज्यिक केन्द्रों के मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करने जैसे मुख्य बिन्दुओं पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मास्टर प्लान में पुरानी दिल्ली से थोक कारोबार की गतिविधियों को बाहर ले जाने की भी योजना रखी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार मसौदे को बुधवार को सार्वजनिक कर दिया गया। इसके लिये 45 दिनों के भीतर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। मसौदे में प्रदूषण को लेकर चिंता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुख

करना, ज्ञान आधारित और उच्च तकनीक उद्योग, उद्यमशीलता गतिविधियों, रियल्टी बाजार, पर्यटन, आतिथ्य, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया है। मसौदे में 24 घंटे वाले शहर की परिकल्पना, मॉडल दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2015 के साथ-साथ रात के समय की अर्थव्यवस्था नीति अवधारणा पर जोर दिया गया है। मास्टर प्लान में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधि और मनोरंजन के विकल्पों को चिन्हित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मसौदे में कहा गया कि शहर के वाणिज्यिक केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र आधारित सुधार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके अलावा कनॉट प्लेस और उसके आस-पास के इलाकों को विरासत और ऐतिहासिक इमारतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी तरह स्थानीय व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेयरहाउसिंग और होटलों की अनुमति देते हुए पुराने इलाके जैसे सदर बाजार के निकट के क्षेत्रों को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। डीडीए अलग-अलग इलाकों को आर्थिक वृद्धि क्षेत्र, क्लीन-टेक इनोवेशन क्लस्टर, चिकित्सीय शहर, शिक्षा शहर के रूप में भी चिन्हित करेगा। हरित अर्थव्यवस्था के लिए हरित विकास क्षेत्र (जीडीए) को एक अलग तैयार किया जायेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।